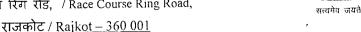


## ::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कः: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,



Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142

Email: cexappealsrajkot@gmail.com



रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

अपील / फाइल संख्या / Appeal / File No.

an

V2/180/GDM/2017 V2/180/GDM/2017 मूल आदेश सं /

टिनांक /

Date

07/UrbanRef/2017-18 07/UrbanRef/2017-18

21-08-2017 21-08-2017

अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): ख

## KCH-EXCUS-000-APP-128-TO-129-2018-19

आदेश का दिनांक /

जारी करने की तारीख/ Date of issue:

10.09.2018

Date of Order:

06.09.2018

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित / Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरित्यित जारी मूल ग आदेश से सृजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Sefvice Tax, Raikot / Jamnagar / Gandhidham :

ਬ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-M/s Bharat Chemical, Shah Avenue- I, Office No. 2, Ward 12B, Gandhidham, Kutch.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुक्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुक्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नित्यित जगह की जा सकती है ।/ Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate "tubunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance (A) Act. 1994 an appeal lies to:-

वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीतीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर- के. पुरन, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/ (i)

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, , द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावां अहमदाबाद- ३८००१६ को की जानी चाहिए ।/ To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above (ii)

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुक्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुक्क की माँग ,व्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुक्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुक्क मा स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिन से अब द्वारा अभी रेप्तिक से स्थाप की शाखा में होना चाहिए । संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा कियत है । स्थापन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुक्क जमा करना होगा ।/ (iii)

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/-Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतिथों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ह्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुरूक की प्रति संबंधित जमा शुरूक की प्रति संबंधित शुरूक का भगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक झाण्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित झण्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित हैं। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन व के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुरूक जमा करना होगा।/ (B)

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं (i) 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुक्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में सलग्न करनी होगी। The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeais) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया अप, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जना कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो। (ii)

कन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है धारा 11 डी के अंतर्गत रकम

- सेनवेट जमा की ती गई गतत राशि (ii)
  - सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (जं- 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D:
  - amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority oner to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C)

(ii)

भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one (i) warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को नियात कर रहे भाल के विभिन्नाण ए प्युक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in (ii) the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। (iii) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गईं है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न- 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में (iv)
  - Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतिया संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / (v)

सर्वित की जीनी चाहर। / The above application State be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्निलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए । जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए । The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश हैं तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपौलीय नयाधिकरण को एक अपौल या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय १९६६ आंधोलगम, 1975, के अनुसूचीन के अनुसार मूल आदेश एवं स्थान आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुक्क टिकिट लेगा हाम चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करते वाले नियमों की और भी ध्याम आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)
- उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं । / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may (G) refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

## :: ORDER IN APPEAL ::

M/s. Bharat Chemical, Shah Avenue-I, Office No. 2, Ward-12/B, Gandhidham, Kutch (hereinafter referred to as "Appellant") has filed appeals against Orders-In-Original No. 06/UrbanRef/2017-18 and 07/UrbanRef/2017-18 both dated 21.08.2017 (hereinafter referred to as "the impugned orders") passed by the Assistant Commissioner, CGST Gandhidham Urban Division, Gandhidham (hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority"). Since the issue involved is common in nature and connected with each other, the same are taken up together for disposal.

Sr. No.	Order-in-Original No. & Date	Amount of refund Rs.	Period Involved
01	06/UrbanRef/2017-18 & 21.08.2017	4,85,924/-	January, 2017
02	07/UrbanRef/2017-18 & 21.08.2017	2,33,562/-	February & March, 2017

- 2. Briefly stated facts of the case are that the Appellant filed refund applications of service tax paid under Notification No. 41/2012-Service Tax dated 29.06.2012 being services consumed for export (supply of fuel to foreign going vessels) which was exempted. The lower adjudicating authority rejected refund claims inter alia, on the following grounds that (i) supplied Fuel (bunker) to the vessel which arrived at the port and (ii) on going through relevant invoices and shipping bills it was found that no goods were exported. The lower adjudicating authority, accordingly, rejected the aforesaid refund claims under Notification No. 41/2012-ST dated 29.06.2012
- 3. Being aggrieved with the impugned orders, the appellant preferred the present appeals on the grounds that the impugned orders rejecting refund claims cannot be sustained as the same have been passed without serving defect memo, without issuing Show Cause Notice and without granting personal hearing in violation of principles of natural justice.
- 4. Shri Vikas Mehta Consultant, during personal hearing reiterated the grounds of Appeal and submitted copies of Shipping Bills to show that the ships were on foreign run and they supplied Bunker, hence needs to be treated as export as the goods have gone from India to outside India albeit as Bunker with the ship to be consumed on the way etc.; that claim was also made under

- 4 -

Notification No. 41/2012-ST and hence, refund should be allowed; on being asked to submit evidences to prove that the ships were actually on foreign run, he requested for some time.

- 4.1 The appellant vide letter dated 22.08.2018 has submitted further written submissions, *interalia*, as under:
- (i) They supplied fuel oil to vessels which were on foreign run and undisputedly sailed outside India and thus, fuel oil was also exported. This makes them eligible for refund of service tax borne by them on input services used in connection with exporting such fuel oil.
- (ii) They submitted all Shipping Bills covered by the impugned orders along with letter of Shipping Agent addressed to the jurisdictional custom authorities duly containing declaration that the vessel is on foreign run and is arriving at Cochin port for bunkering purpose; that they relied upon Trade Facility No. 17/2013 issued by Custom House, Kochi laying down procedure for supply of fuel to vessels on foreign run that was issued specifically for promoting Cochin Port as Bunkering Port and they abided by the procedure laid down in this Trade Facility Notice; that there is no dispute that the vessels along with fuel oil have undertaken voyage from India to outside India, in other words, there is no dispute that fuel oil supplied by them was exported.

## **Findings:**

- 5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the grounds of appeal and submissions made by appellant. The issue to be decided in the present appeal is as to whether the impugned orders passed by the adjudicating authority rejecting the refund claims of Service Tax paid on the services for export of the goods under Notification No. 41/2012-St dated 29.06.2012 is correct or otherwise.
- 6. I find that the Appellant filed refund applications of service tax paid under Notification No. 41/2012-Service Tax dated 29.06.2012 on services consumed for export (i.e. supply of fuel to foreign going vessels), however, the lower adjudicating authority rejected refund claims on the ground that the Appellant supplied fuel to the vessels and no goods were exported even though fuel was supplied to the vessels under shipping bills. The Appellant

submitted that the said vessels were on foreign run and thus, the supplied fuel has to be treated as exported making them eligible for refund of service tax borne by them on the input services used in connection with the exporting of fuel.

- 6.1 The Appellant had submitted respective Shipping Bills covered under the impugned orders along with letters of Shipping Agent addressed to the Jurisdictional Custom Authorities. On scrutiny of the said documents, I find that these vessels had arrived at Cochin Port for bunkering purpose and were on the foreign run. Thus, the vessels undisputedly sailed from Cochin Port to the places outside India and it is a fact that such supplied fuel to the vessels also sailed with the vessel to a place outside India and hence exported. Therefore, I hold that the fuel supplied to the vessels were exported from Cochin Port to outside India under the respective Shipping Bills since the above stated facts are not in dispute. The rejection of refund claims is therefore, not sustainable in view of the judgment of the Hon'ble Madras High Court in the case of M/s. Tablets India Ltd. reported as 2010 (259) ELT 191 (MAD) wherein the Hon'ble High Court has held that "when factum of export is not doubted, rebate cannot be denied even if all the conditions of the notification are not complied with". Mrn()
- I further rely on the judgment of the Hon'ble Madras High Court in the case of Ford India Pvt. Ltd. reported as 2011 (272) E.L.T. 353 (Mad.) and the Government of India's order in the case of Modern Process Printers reported as 2006 (204) E.L.T. 632 (G.O.I.) holding that the rebate/drawback and other such export promotion schemes of the Government are incentive schemes intended to promote export and to earn foreign exchange for the country and if export of services is not in doubt, a liberal interpretation is required to be taken in case of technical lapses. By applying the ratio of the above decisions to the facts of the present case and considering that the services have actually been used in export of goods, I am of the view that denial of refund of cenvat credit of service tax paid on the input services is not correct and proper.
- 7. I, therefore, have no option but to hold that the supplied fuel as bunker to foreign going ships has to be treated as export and the Appellant is eligible for refund of service tax paid by them on input services used in relation to export of such fuel in terms of Notification No. 41/2012-ST dated 29.06.2012. Hence, the

impugned orders rejecting refund claims are not correct and require to be set aside.

- 6 -

- 8. In view of above, I set aside the impugned orders and allow the appeals with consequential relief.
- ९. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपीस्ल का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

· 中市(四氢双)

9. The appeals filed by the appellant are disposed off in above terms.

QHM1019/18

(कुमार संतोष) 6/9/20% आयुक्त (अपील्स)

By R.P.A.D.

To,

M/s. Bharat Chemical, Shah Avenue-I, Office No. 2, Ward-12/B, Gandidham, Kutch.

मे. भारत केमिकल, शाह एवेन्यू-1, ऑफिस नं. 2, वोर्ड नं. 2, गांधीधाम, कच्छ.

Copy for information and necessary action to:

- 1) The Chief Commissioner, CGST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad for kind information.
- 2) The Commissioner, CGST & Central Excise, Gandhidham, Kutch.
- 3) The Assistant Commissioner, CGST & Central Excise Division, Gandhidham, Kutch.

(A) Guard File.

5) F. No. V2/181/GDM/2017